lives of lakhs of people. The problem is regarding working of the Jhilmil District of the Delhi Electric Supply Undertaking.

The lighting arrangements even on the main roads of national importance like the G.T. Road from the old Yamuna Bridge upto the U.P. border are very inadequate.

There are no lights on the road beyond Preet Vihar to Anand Vihar and U P. border. This is in spite of the fact that the I and B Minister himself has assured the residents of the area that this would be done shortly. However, no action has been taken so far by DESU.

Domestic connections to the intending small house builders of the approved colonies are very much delayed.

There is too much delay in installing connections even when all the necessary facilities are provided by the consumers

The maintenance of the street lights in colonies like Yojana Vihar is so poor that this has caused a lot of fear in the minds of the residents about their proper security. This is so in spite of many written complaints.

The engineers and the officers of the Jhilmil District are hardly available in their rooms most of the time and the reply given is that they have gone for site inspection.

I, therefore, suggest that a high level inquiry be conducted into the working of the Jhilmil district. Unless, this is done immediately, I am afraid that the situation would worsen day by day.

**(iv) Financial help to Rajasthan Government for repairs of roads damaged due to military exercises**

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं गंगानगर जिलो मे थल सेना का सैनिक अभ्यास कार्य करीब 15 वर्षो से सर्दी के दिनों में प्रतिवर्ष चल रहा है। थल सेना अभ्यास के समय बड़े-बड़े वाहनो, टैकरों आदि का प्रयोग करती है। उक्त वाहनों के प्रयोग के कारण राज्य की सैंकड़ों सड़कें तहस-नहस एवं क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके कारण राज्य को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है।

राज्य की जनता का आवागमन मे बाधा के कारण बड़े कष्ट का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की नही है, जो प्रतिवर्ष उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य हाथ में ले।

अत: केन्द्र सरकार के रक्षा विभाग से निवेदन है कि वे अपने प्रतिनिधि को तुरन्त मौके पर भेजें और राज्य सरकार के प्रतिनिधि को साथ में लेकर सम्पूर्ण नुकसान का पता लगाकर राज्य सरकार को मुआवजे के रूप में तुरन्त से तुरन्त राशि प्रदान कराएं, ताकि गर्मी की वर्षा से पहले-पहले उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य संपूर्ण किया जा सके।

**14.37 hrs.**

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

**(v) Need to restore the earlier admission policy in J.N.U.**

**श्री बी०डी० सिंह** (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 1973 में प्रवेश की एक ऐसी नीति को स्वीकृति किया था एवं सत्र 1974-75 से क्रियान्वित किया था, जिससे निर्बल वर्ग के तथा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तथा पिछड़े क्षेत्रों के परिवारों के छात्रों को विशेष सुविधा प्रदान करके उन्हे विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सुलभ कर दिया जाता था। परन्तु अभी हाल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने निर्णय लेकर उस प्रवेश नीति को समाप्त कर दिया। इसका परिणाम यह होगा कि उन छात्रों को, जो सामाजिक, आर्थिक अथवा क्षेत्रीय दृष्टि से पिछड़े है, प्रवेश के समय अंकों में वह छूट नहीं प्रदान की जाएगी, जो पूर्व प्रवेश नीति के अन्तर्गत प्रदान की जाती थी।

ऐसा कहा जाता है कि उस नीति से शिक्षा के स्तर में ह्रास हुआ है, जो वास्तविकता से परे है। डाक्टर जाकिर हुसैन सैन्टर फार एजुकेशनल स्टडीज, जे०एन०यू०, के एक अध्ययन के परिणाम-स्वरूप विदित हुआ है कि इन पिछड़े वर्गों से आये छात्रों का अध्ययन कार्य एवं उनकी क्षमता कहीं अच्छी रही है। प्रवेश की प्रगतिशील नीति छात्रों, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालीय समितियों के पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् निर्धारित की गई थी, परन्तु उसे समाप्त करते समय विस्तृत विचार-विमर्श नहीं किया गया।

मैं माननीया शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश की पूर्व नीति को बरकरार रखा जाए। उस नीति के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए एक समिति जिसमें छात्रों, शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय की समितियों का प्रतिनिधित्व हो, बनाई जाए, जो नीति का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करके सुझाव दे।

**(vi) Stagnation in promotion avenues of engineers in Bokaro Steel Plant**

*SHRI RASA BEHARI BEHERA (Kalahandi) : The future of 983 engineers in the project wing of the Bokaro Steel Plant hangs in a balance following "total stagnation" in their promotional avenues. The promotion of the project engineers of the B.S.P. was held up for more than nine years in one grade while they still handled project works valued at Rs. 1200 crores.

The project engineers have already taken up the expansion of the BSP, which is to be completed by 1986, but it is regrettable that SAIL management has not planned for their future deployment.

In view of the above, I suggest that the Government should set up a central project division immediately for the Steel Authority of India Limited to pool them. The Centre and SAIL should also deploy them in other expanding organisations like the NTPC to open up job opportunities for them. I request the Government of India to take immediate steps in the above matter.

**(vii) Increasing number of accidents at Gandhi Setu, Patna**

**श्री राम विलास पासवान** : (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान 1 फरवरी को घटी अत्यन्त ही हृदय विदारक घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। 1 फरवरी को 9 बजे सबेरे महात्मा गांधी सेतु (पटना-हाजीपुर गंगापुल) पर एक मिनी बस रेलिंग तोड़ कर पुल के नीचे चली गई जिसमें 49 व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गई। मृतकों में से अधिकांश मेरे क्षेत्र के ही थे। यह बिहार राज्य की सबसे बड़ी बस दुर्घटना है। जब से इस पुल का निर्माण हुआ है तबसे बस, ट्रक एवं बैलगाड़ी की दुर्घटनाओं की बाढ़ लग गयी है। कोई ऐसा महीना नहीं जाता है जिस महीने में दुर्घटना नहीं होती हो और लोगों की जान नहीं जाती हो। दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो अभी तक पुल का एक ही हिस्सा पूरा हो पाया है, दूसरा, दोनों तरफ पुल का रेलिंग इतना कमजोर है कि थोड़ा सा ठोकर लगने के बाद वह टूट कर नीचे गिर जाता है। जो बस या मिनी बस बिहार में चलती है उसमें क्षमता से कई गुने अधिक यात्रियों को चढ़ा लिया जाता है और गति सीमा से अधिक रफ्तार से गाड़ी लापरवाही से चलाई जाती है। पिछले 23 महीनों में 200 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। बिहार सरकार द्वारा मृतक परिवारों को जो राशि दी जाती रही है वह नगण्य है।

अतः केन्द्र सरकार से मांग है कि अधूरे पुल को अविलम्ब पूरा करें, दोनों तरफ के रेलिंग को मजबूत किया जाय, क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोने वाले एवं गति सीमा से अधिक चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय एवं प्रत्येक मृतक परिवारों को समुचित मुआवजा दिया जाय।

*Original speech was delivered in Oriya.